



- ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा है कि द्वीपों में सरकार की सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में सहयोग देने के लिए तीन निजी अस्पतालों को सम्मानित किया गया है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वह मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य सुधार योजना-बीआरएपी दो हजार चौबीस लागू करेगी।
- राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान हैदराबाद की ओर से द्वीपसमूह में डाईट और भारतीय बायोमार्कर सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा।
- विद्युत विभाग का गाराचरमा साईट कार्यालय कल से कार्य करना आरंभ कर देगा।



ग्रामीण विकास, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा है कि द्वीपों में सरकार की सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कहा कि समुदायों को शामिल कर योजनाओं के लाभ के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न की जा रही है, ताकि लोग इनका लाभ उठा सकें।



अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में सहयोग देने के लिए तीन निजी अस्पतालों को सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में विशेष सचिव स्वास्थ्य और संघशासित स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अनिल अग्रवाल ने इन संस्थानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें अरुण अस्पताल डॉलीगंज, स्वास्थ्य मेडिकल सेन्टर भातुबस्ती और चेन्नई श्री बालाजी स्कैन सेन्टर फीनिक्स बे शामिल है। द्वीपों में इन तीनों निजी अस्पतालों द्वारा अभियान के तहत निशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। इनके अलावा दस निजी डॉक्टरों ने भी पिछले वर्ष नौ मार्च से स्वैच्छिक रूप से सेवाएं प्रदान करने के लिए शपथ ली है। ये योजना द्वीपसमूह में नौ सितम्बर दो हजार सोलह में शुरू की गई थी और प्रत्येक महीने के नौ तारीख को चिन्हित सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। योजना की स्थापना से लेकर अब तक उनतीस हजार पांच सौ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है और निजी डॉक्टरों द्वारा तीन सौ से अधिक परामर्श सेवाएं तथा अल्ट्रा सोनोग्राफी प्रदान की गई है।

<><><><><><>

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वह मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करने के लिए व्यापक कार्य सुधार योजना—बीआरएपी दो हजार चौबीस लागू करेगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस योजना से कारोबारी प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, नियमों के अनुपालन का बोझ कम होगा और डिजिटल समाधान के जरिये भारत को पसंदीदा वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने का





